कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान
शासन सचिवालय, जयपुर

क्रमांकः– प. 8(2)(2)निर्वा./2018/ 541 **जयपुर, दिनांक :– 2/2/2023**

प्रेषकः– मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

प्रेषितः– समस्त मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दलों की राज्यीय इकाई, राजस्थान।

राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, राजस्थान।

पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल,
राजस्थान।

विषयः– **Misuse of religious institutions for political purposes – regarding.**

प्रसंगः– भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली का पत्र कमांक No.3/1/2022/SDR/Vol.I दिनांक 19.01.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली ने अपने प्रासंगिक पत्र दिनांक 19.01.2023 (प्रति संलग्न) के क्रम में अपने पूर्व निर्देश दिनांक 27.07.2012 को दोहराते (**Reiterate**) हुए अवगत कराया है कि राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता के मौजूदा प्रावधान किसी भी तरह से चुनाव प्रचार के मंच के रूप में पूजा स्थलों के उपयोग पर रोक लगाते है।

इसके अतिरिक्त धार्मिक संस्थान (**Prevention of Misuse**) अधिनियम, 1988 (1988 की संख्या 41) की धारा 3, 5 एवं 6 किसी भी राजनीतिक विचारों या राजनीतिक गतिविधि के प्रचार या प्रचार के लिए धार्मिक संस्थानों या धार्मिक संस्थानों के धन के उपयोग पर रोक लगाती है। किसी भी राजनीतिक दल के हित में इनमें से किसी भी धारा के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर 5 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है।

भारत निर्वाचन आयोग की इच्छा है कि मौजूदा कानून के उपरोक्त प्रावधानों को सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों/रिटर्निंग ऑफिसरों के ध्यान में लाया जाये ताकि यह सुनिश्चित किया जा सकें कि चुनाव के दौरान इन प्रावधानों के किसी भी उल्लंघन से सख्ती से निपटा जा सके और धार्मिक संस्थानों (**Prevention of Misuse**) अधिनियम, 1988 की उक्त धाराओं के तहत् किसी भी अपराध/घटना में संबंधित प्रावधानों के तहत् एफआईआर/शिकायतें दर्ज की जा सकें।

अतः इस संबंध में निवेदन है कि आयोग के प्रासंगिक पत्र दिनांक 19.01.2023 एवं 27.07.2012 के दिशा–निर्देश चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के ध्यान में लाये जाकर अक्षरशः पालना सुनिश्चित कराये जाने का श्रम करावें।

भवदीय,

(कृष्ण कुणाल)
अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान
शासन सचिवालय, जयपुर

क्रमांकः— प. 8(2)(2)निर्वा./2018/542 **जयपुर, दिनांक :— 2/2/2023**

प्रेषकः— मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

प्रेषितः— समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर्स) राजस्थान।

विषयः— **Misuse of religious institutions for political purposes – regarding.**

प्रसंगः— भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली का पत्र कमांक No.3/1/2022/SDR/Vol.I दिनांक 19.01.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली ने अपने प्रासंगिक पत्र दिनांक 19.01.2023 (प्रति संलग्न) के कम में अपने पूर्व निर्देश दिनांक 27.07.2012 को दोहराते (**Reiterate**) हुए अवगत कराया है कि राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता के मौजूदा प्रावधान किसी भी तरह से चुनाव प्रचार के मंच के रूप में पूजा स्थलों के उपयोग पर रोक लगाते है।

इसके अतिरिक्त धार्मिक संस्थान (**Prevention of Misuse**) अधिनियम, 1988 (1988 की संख्या 41) की धारा 3, 5 एवं 6 किसी भी राजनीतिक विचारों या राजनीतिक गतिविधि के प्रचार या प्रचार के लिए धार्मिक संस्थानों या धार्मिक संस्थानों के धन के उपयोग पर रोक लगाती है। किसी भी राजनीतिक दल के हित में इनमें से किसी भी धारा के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर 5 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है।

भारत निर्वाचन आयोग की इच्छा है कि मौजूदा कानून के उपरोक्त प्रावधानों को सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों/रिटर्निंग ऑफिसरों के ध्यान में लाया जाये ताकि यह सुनिश्चित किया जा सकें कि चुनाव के दौरान इन प्रावधानों के किसी भी उल्लंघन से सख्ती से निपटा जा सके और धार्मिक संस्थानों (**Prevention of Misuse**) अधिनियम, 1988 की उक्त धाराओं के तहत् किसी भी अपराध/घटना में संबंधित प्रावधानों के तहत् एफआईआर/शिकायतें दर्ज की जा सकें।

अतः निवेदन है कि आयोग के प्रासंगिक पत्र दिनांक 19.01.2023 एवं 27.07.2012 के दिशा—निर्देशों को आपके जिले की समस्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारियों एवं चुनाव संबंधित अन्य समस्त अधिकारियों के ध्यान में लाये जाकर अक्षरशः पालना सुनिश्चित करावें।

<u>संलग्न :— उपरोक्तानुसार।</u>

भवदीय,

(कृष्ण कुणाल)
अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

D/CPM/VSE-2018/8.2.2.2018

क्रमांकः– प. 8(2)(2)निर्वा./2018/542   जयपुर, दिनांक :– 2.02.2023

प्रतिलिपि निम्न को भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के प्रासंगिक पत्र दिनांक 19.01.2023 एवं 27.07.2012 की छायाप्रति संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

1. मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान।
6. विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए समस्त रिटर्निंग ऑफिसर।
7. प्रभारी अधिकारी, एम.सी.सी. शाखा, निर्वाचन विभाग, राजस्थान।

विशेषाधिकारी,
निर्वाचन विभाग
राजस्थान, जयपुर।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

No. 3/1/2022/SDR/Vol.I **Dated: 19th January, 2023**

To,

The Chief Electoral officers of
All States/UTs

Sub: - Misuse of religious institutions for political purposes-regarding.

Sir/Madam,

I am directed to refer to the subject cited above and to reiterate the Commission's direction issued vide letter no. 3/1/2012-SDR dated 27th July, 2012 whereby the Commission directed that the existing provisions of the Model Code of Conduct for the guidance of political parties and candidates, prohibit the use of places of worship as forum for election propaganda in any manner.

Further, Sections 3, 5 & 6 of The Religious Institutions (Prevention of Misuse) Act, 1988 (No. 41 of 1988) prohibit use of religious institutions or funds of religious institutions for the promotion or propagation of any political ideas or political activity or for the benefit of any political party. Contravention of the provisions of any of these Sections is punishable by imprisonment upto 5 years and with fine. (Copy enclosed)

The Commission desires that the above provisions of the existing law may be brought to the notice of all DEOs and ROs so as to ensure that any violation of these provisions during election is dealt with firmly and FIRs/ complaints are lodged under relevant provisions in the event of any offence under the said Sections of the Religious Institutions (Prevention of Misuse) Act, 1988.

DEOs, ROs and other election authorities should be instructed to ensure strict observance of the above provisions of law. This may also be circulated to all political parties based in your State/ UT, including State units of the political parties for their information.

Kindly acknowledge receipt.

Yours faithfully,

NARENDRA N. BUTOLIA
(Sr. Principal Secretary)

Copy to: The President/General Secretary of all recognized National and State parties (As per list attached).

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

No. 3/1/2012-SDR Dated: 27th July, 2012

To,

The Chief Electoral officers of
all States/ UTs
(*except Jammu & Kashmir*)

Sub:- Misuse of religious institutions for political purposes –regarding.

Sir/Madam,

The existing provisions of the Model Code of Conduct for the guidance of political parties and candidates prohibit the use of places of worship as forum for election propaganda in any manner.

Further, Sections 3, 5 & 6 of The Religious Institutions (Prevention of Misuse) Act, 1988 (No. 41 of 1988) prohibit use of religious institutions or funds of religious institutions for the promotion or propagation of any political ideas or political activity or for benefit of any political party. Contravention of the provisions of any of these Sections is punishable by imprisonment upto 5 years and with fine.

The Commission desires that the above provisions of the existing law may be brought to the notice of all DEOs and ROs so as to ensure that any violation of these provisions during election is dealt with firmly and .FIRs/ complaints are lodged under relevant provisions in the event of any offence under the said Sections of the Religious Institutions (Prevention of Misuse) Act, 1988.

A copy of the above mentioned Act (No. 41 of 1988) is enclosed herewith. DEOs, ROs and other election authorities should be instructed to ensure strict observance of the above provisions of law. This may also be circulated to all political parties based in your State/ UT, including State units of the political parties for their information.

Kindly acknowledge receipt.

Yours faithfully,

(Ashish Chakraborty)
Secretary

Copy to: The President/General Secretary of all recognized National and State parties (As per list attached).

रजिस्ट्री सं० डी (डीएन) 127/88 REGISTERED NO. D (DN) 127/88

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड I
PART II —Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 57] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर, 2, 1988/भाद्र 11, 1910
No. 57] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 2, 1988/BHADRA 11, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ट संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(Legislative Department)
New Delhi, the 2nd September, 1988/Bhadra 11, 1910 (Saka)

The following Act of Parliament received the assent of the President on the 1st September, 1988, and is hereby published for general information :-

THE RELIGIOUS INSTITUTIONS (PREVENTION OF MISUSE) ACT, 1988

No. 41 OF 1988

[1st September, 1988.]

An Act to prevent the misuse of religious institutions for political and other purposes.

BE it enacted by Parliament in the Thirty-ninth Year of the Republic of India as follows:-

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Religious Institutions (Prevention of Misuse) Act, 1988.

(2) It extends to the whole of India except the State of Jammu and Kashmir.

(3) It shall be deemed to have come into force on the 26th day of May, 1988.

Definitions.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,-

54 of 1959. (a) "ammunition" shall have the same meaning as in clause (b) of sub-section (1) of section 2 of the Arms Act, 1959.

(b) "arms " shall have the same meaning as in clause (c) of sub-section (1) of section 2 of the Arms Act, 1959. 54 of 1959

(c) "manager", in relation to a religoius institution, means every person, including any religious functionary (by whatever name called), Who, for the time being, either alone or in association with other persons, administers, managers or otherwise controls the affairs of that institution, its functions or properties.

(d) "political activity" includes any activity promoting or propagating the aims or objects of a political party or any cause, issue or question of a political nature by organising meetings, demonstrations, processions, collection or disbursement of funds, or by the issue of disretions or decrees, or by any other means, and includes also such activity by or on behalf of a person seeking election as a candidate for any election to Parliament, any State Legislature or any local authority.

(e) "political party" means an association or body of persons-

(i) which is, or is deemed to be, registered, with the Election Commission of India as a political party under the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968, as in force for the time being. or

(ii) which has set up candidates for election to any legislature, but is not registered, or deemed to be registered, as a political party, under the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968. or

(iii) organised to carry on any political activity or to acquire or exercise political power through election or otherwise.

(f) "religious institution" means an institution for the promotion of any religion or persuasion, and includes any place or premises used as a place of public religious worship, by whatever name or designation known.

Prohibition of use of religious institutions for certain purposes,

3. No religious institution or manager thereof shall use or allow the use of any premises belonging to, or under the control of, the institution-

(a) for the promotion or propagation of any political activity. or

(b) for the harbouring of any person accused or convicted of an offence under any law for the time being in force; or

(c) for the storing of any arms or ammunition. or

(d) for keeping any goods or articles in contravention of any law for the time being in force. or

(e) for erecting or putting up of any construction or fortification, including basements, bunkers, towers or walls without a valid licence or permission under any law for the time being in force; or

(f) for the carrying on of any unlawful or subversive act prohibited under any law for the time being in force or in contravention of any order made by any court. or

(g) for the doing of any act which promotes or attempts to promote disharmony or feelings of enmity, hatred or ill-will between defferent religious, racial, language or regional groups or castes or communities. or

(h) for the carrying on of any activity prejudicial to the sovereighty, unity and integrity of India. or

(i) for the doing of any act in contravention of the provisions of the Prevention of Insults to National Honour Act, 1971.

69 of 1971.

4. No religious institution or manager thereof shall allow the entry of any arms or ammunition or of any peson carrying any arms or ammunition into the religious institution :

Restrictions on carrying arms and ammunition into a religious institution.

Provided that nothing in this section shall apply to-

(a) the wearing and carrying of a kirpan by any person professing the Sikh religion. or

(b) any arms which are used as part of any religious ceremoney or ritual of the institution as established by custom or usage.

5. No religious institution or manager thereof shall use or allow the use of any funds or other properties belonging to, or under the control of, the institution for the benefit of any political party or for the purpose of any political activity or for the commission of any act which is punishable as an offence under any law.

Prohibition of use of funds of religious institutions for certain activities.

6. No religious institution or manager thereof shall allow any ceremony, festivel, congregation, procession or assembly organised or held under its auspices to be used for any political activity.

Prohibition of religious fora for propagating political ideas.

7. Where any religious institution or manager thereof contravenes the provisions of section3, section 4, section 5 or section 6, the manager and every person connected with such contravention shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to five years and with fine which may extend to ten thousand rupees.

Penalties.

8. (1) Any manager or other employee of a religious institution shall, upon conviction for an offence under this Act, stand removed from his office or post and shall, notwithstanding anything to the contrary contained in any other law, be disqualified for appointment in any religious institution as manager or in any other capacity for a period of six years from the date of his conviction.

Disqualification of persons convicted or charge-sheeted under this Act.

(2) Where any manager or other employee of a religious institution is accused of an offence under this Act and a charge-sheet for the prosecution of such person is filed in any court and the court is of the opinion, after considering the charge-sheet and after hearing the prosecution and the accused, that a prima facie case exists, it shall pass an order or direction restraining the person from exercising the powers or discharging the duties of his office or post pending trial.

(3) Where any manager or other employee has been removed under sub-section (1), or restrained under sub-section (2), the vacancy arising out of such removal or restraint may be filled in the manner provided in the law applicable to the said religious institution.

Certain persons bound to give information to police.

9. Every manager or other employee of a religious institution shall be bound to give information to the officer incharge of the police station within whose local jurisdiction the religious institution is situated of any contra vention or any impending contravention of the provisions of this Act and any failure to do so shall be punishable under section 176 of the Indian Penal Code. 45 of 1860

Repeal and saving.

10. (1) The Religious Institution (Prevention of Misuse) Ordinance, 1988 is hereby repealed. Ord. 3 of 1988

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

S. RAMAIAH,
Secy. to the Govt. of India.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS. MINTO ROAD, NEW DELHI
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS. DELHI, 1988

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोका रोड, नई दिल्ली- 110001

मि.सं.3/1/2012-एसडीआर

दिनांक- 27 जुलाई, 2012

सेवा में,

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों
के मुख्य निर्वाचन अधिकारी
(जम्मू एवं कश्मीर के अतिरिक्त)

विषय- राजनैतिक प्रयोजनार्थ धार्मिक संस्थाओं के दुरुपयोग- के संबंध में।

महोदय/महोदया,

राजनैतिक दलों तथा अभ्यर्थियों के मार्गनिर्देशन के लिए आदर्श आचार संहिता के विद्यमान प्रावधान, पूजा स्थलों के किसी भी प्रकार के निर्वाचन प्रचार के लिए मंच हेतु प्रयोग का निषेध करते है।

इसके अतिरिक्त, धार्मिक संस्था (दुरुपयोग निवारण) अधिनियम, 1988 (1988 का 41) की धारा 3,5 तथा 6 किसी राजनैतिक दल के लाभ या किसी राजनैतिक विचार अथवा राजनैतिक गतिविधि के लिए धार्मिक संस्थाओं या धार्मिक संस्थाओं की निधि का प्रयोग निषिद्ध करती है। इन धाराओं के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन पर 5 वर्ष तक का कारावास या जुर्माने द्वारा दंड दिये जाने का प्रावधान है।

आयोग चाहता है कि विद्यमान विधि के उपरोक्त प्रावधानों को सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों तथा रिटर्निंग आफिसरों के ध्यान में लाया जाए ताकि वे यह सुनिश्चित कर सकें कि निर्वाचन के दौरान इन प्रावधानों के उल्लंघन से कड़ाई से निपटा जाए तथा धार्मिक संस्था (दुरुपयोग निवारण) अधिनियम, 1988 की उपरोक्त धाराओं के अंतर्गत किसी अपराध होने की स्थिति में सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट/शिकायत दर्ज की जाए।

उपरोक्त अधिनियम (1988 की सं. 41) की एक प्रति एतदद्वारा संलग्न है। जिला निर्वाचन अधिकारियों, रिटर्निंग आफिसरों तथा अन्य निर्वाचन प्राधिकारियों को विधि के उपरोक्त प्रावधानों के कड़े अनुपालन सुनिश्चित करने के अनुदेश दिए जाने चाहिए। इसे आपके राज्य/संघ राज्य क्षेत्र आधारित राजनैतिक दलों, जिनमें राजनैतिक दलों के राज्य एकक भी शामिल हों, को सूचनार्थ भी परिचालित किया जाए।

कृपया प्राप्ति सूचना दें।

भवदीय,
आशीष चक्रवर्ती
(आशीष चक्रवर्ती)
सचिव

प्रतिलिपि- सभी मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय तथा राज्यीय दलों के अध्यक्ष/महासचिव (संलग्न सूची के अनुसार)